



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10 1971/अग्रहायण 19, 1893

No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1971/AGRAHAYANA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December 1971

G.S.R. 1868.—It is hereby notified that the following clause of the license to establish, maintain and work wireless telegraph in ships registered in India is in operation with immediate effect:—

- “(1) If and whenever, an emergency shall have arisen in which it is expedient for the public service that the President of India (hereinafter called the President) shall have control over the transmission of messages by the licensed apparatus, it shall be lawful for the Central Government or any agent authorised in writing in that behalf by them to cause the Station or any part thereof to be taken possession of in the name and on behalf of the President and to be used for such services as the Central Government may require and in that event any officer authorised by the Central Government may enter the Station and take possession of and use the same as aforesaid.

(2) The Central Government or their authorised agent may:—

- (a) instead of taking possession of the Station as aforesaid, direct and authorise such persons as he may think fit to assume control of the transmission and reception of messages at the Station either wholly or partly and in such manner as he may direct and such persons may accordingly enter the Station and assume such control;
 - (b) direct that all or any class or classes of messages tendered for transmission or received at the Station shall be handed over to an officer authorised by him;
 - (c) stop or delay the transmission, reception or delivery of any messages tendered for transmission or received at the Station;
 - (d) require the Licensee, to obey all such directions with reference to the transmission or reception of messages at the Station as the Central Government or their agent or any other persons authorised by the Central Government may prescribe and the Licensee shall obey and conform to all such directions.
- (3) The Licensee shall be entitled to reasonable compensation to be fixed by a sole arbitrator nominated by the Government whose decision shall be final for any damage to the licensed apparatus arising in consequence of the exercise of the power conferred by this clause.
- (4) In the event of the Licensee refusing to comply with the provisions of sub-clauses—
- (1) and (2) of this clause the Central Government may immediately thereupon cancel the license without the Licensee being entitled to any compensation and without prejudice to any steps the President may think fit to take to obtain possession of such licensed apparatus or to claim damages.

[No. F. R-11016/27/71-I.R.]

N. V. SHENOI, Secy.

संचार मंत्रालय

अधिवृत्ता

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

सा. का. नि. सं. 1863.—एतद्वारा यह अधिवृत्ति किया जाता है कि भारत में पंजीकृत जहाजों में बेसार तार स्थापित करने, बनाये रखने एवं संचालित करने के लिये अनुज्ञप्ति का निम्नलिखित शब्द नत्काल प्रभावी रूप से प्रवर्तन में है—

(1) यदि और जब कभी आपात की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें लोक सेवा के लिये यह मसीखीन हो कि अनुज्ञत साधित्र द्वारा संदेशों के पाठ्येण पर भारत के राष्ट्रपति का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रपति कहा गया है) नियंत्रण हो तो केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अधिकर्ता के लिये, स्टेशनों या उनके किसी भाग का, राष्ट्रपति के नाम में और उसकी और से कब्जा लेना और ऐसी सेवाओं के लिये जैसी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करें प्रयोग करना विधिपूर्ण होगा और उस दशा में केन्द्रीय सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकर्ता स्टेशनों, में प्रयोग कर सकेगा उस पर कब्जा कर सकेगा और उनका पूर्वोक्त रूप से प्रयोग कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकर्ता —

(क) पूर्वोक्त रूप से किसी स्टेशन का कब्जा लेने के बदले ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे निविष्ट और प्राधिकृत कर सकेगा कि वह स्टेशन या स्टेशनों में संदेशों के पारे-बण और प्राप्ति का नियंत्रण पूर्णतः या भागतः और ऐसी रीति में जैसी वह निविष्ट करे संभाल ले और ऐसे व्यक्ति तदनुसार स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे और ऐसा नियंत्रण सम्भाल सकेंगे ;

(ख) निदेश दे सकेगा कि किसी स्टेशन पर पारेबण के लिये दिये गये या प्राप्त किये गये सभी या किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के संदेश ऐसे अधिकारी को वे दिये जायेंगे जो उसके द्वारा प्राधिकृत हो ;

(ग) स्टेशनों पर पारेबण के लिये दिये गये या प्राप्त किये गये किन्हीं संदेशों के पारे-बण, प्राप्ति या परिदान को रोक सकेगा या विनियमित कर सकेगा ;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्टेशनों पर संदेशों के पारेबण या प्राप्ति से संबंधित सभी ऐसे निदेशों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार या उसका अधिकर्ता या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति विहित करे, पालन करे और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी निदेशों का पालन करेगा और उनके अनुरूप कार्य करेगा ।

(3) इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्त माधिम होने वाले किसी नुकसान के लिये अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तिगत प्रतिकर का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ताम निर्देशित एकल मध्यस्थ द्वारा नियत किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस खंड के उपखंड (1) और (2) के उपबंधों के अनुपालन से इन्कार किये जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार तुरन्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगी और उससे अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं और न किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों पर प्रति-कूल प्रभाव पड़ेगा जिन्हें राष्ट्रपति ऐसे अनुज्ञप्त साधिम का कब्जा अभिप्राप्त करने के लिये अवदा नुकसानी का दावा करने के लिये करता ठीक समझे ।

[सं० आर० 11016/27/71-एल० आर०]

एन० बी० मेजाय, सचिव ।

